

*राजस्थान सरकार*

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-स03-2(04)स्था/एपीओ/अभि/16 / 12290-91

दिनांक: 18/9/18

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Civil Writ pet. No. 6954/2017 जितेन्द्र कुमार बैरड़ v/s राज0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018 का सम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी के संदर्भ में पूर्व में निदेशालय में गठित कमेटी को राय का भी अवलोकन किया गया।

माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में निर्देशित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अवतार सिंह v/s UOI व अन्य S.L.P. No. 20525/2011 निर्णय दिनांक 21.07.2016 एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय हीरालाल शर्मा v/s State of Rajasthan व अन्य (S.B. सिविल रिट पिटीशन नं0 13087/2016) में दिये गये निर्णयों के प्ररिप्रेक्ष्य में एवं राज0 अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 13 को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी के प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावे।

प्रार्थी जितेन्द्र कुमार बैरड़ द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका ए.पी.ओ. भर्ती 2015 से संबंधित है, प्रार्थी का नाम आर.पी.एस.सी. द्वारा अभिस्तावित किये जाने पर पुलिस चरित्र सत्यापन के दौरान ज्ञात हुआ है कि उसके विरुद्ध थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़ में एफ.आई.आर. नं0 6/14 धारा 498ए, 406, 323, 377 आईपीसी में पंजीबद्ध हुआ था जिसमें दिनांक 29.10.2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निदेशालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के कॉलम सं0 01(vii) को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी कौनियुक्ति हेतु अपात्र माना गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवतार सिंह के मामले में निर्णय के पैरा सं0 30 में निम्नलिखित दिशानिर्देश दिये हैं:-

30. We have noticed various decisions and tried to explain and reconcile them as far as possible. In view of aforesaid discussion, we summarize our conclusion thus:
- (1) Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information.
  - (2) While passing order of termination of services or cancellation of candidature for giving false information, the employer may take notice of special circumstances of the case, if any, while giving such information.
  - (3) The employer shall take into consideration the Government orders/instructions/rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision.

*राजस्थान सरकार*  
18/9/18

(4) In case there is suppression or false information of involvement in a criminal case where conviction or acquittal had already been recorded before filling of the application/verification form and such fact later comes to knowledge of employer, any of the following recourse appropriate to the case may be adopted :-

(a) In a case trivial in nature in which conviction had been recorded, such as shouting slogans at young age or for a petty offence which if disclosed would not have rendered an incumbent unfit for post in question, the employer may, in its discretion, ignore such suppression of fact or false information by condoning the lapse.

(b) Where conviction has been recorded in case which is not trivial in nature, employer may cancel candidature or terminate services of the employee.

(c) If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on technical ground and it is not a case of clean acquittal, or benefit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to antecedents, and may take appropriate decision as to the continuance of the employee.

(5) In a case where the employee has made declaration truthfully of a concluded criminal case, the employer still has the right to consider antecedents, and cannot be compelled to appoint the candidate.

(6) In case when fact has been truthfully declared in character verification form regarding pendency of a criminal case of trivial nature, employer, in facts and circumstances of the case, in its discretion may appoint the candidate subject to decision of such case.

(7) In a case of deliberate suppression of fact with respect to multiple pending cases such false information by itself will assume significance and an employer may pass appropriate order cancelling candidature or terminating services as appointment of a person against whom multiple criminal cases were pending may not be proper.

(8) If criminal case was pending but not known to the candidate at the time of filling the form, still it may have adverse impact and the appointing authority would take decision after considering the seriousness of the crime.


(9) In case the employee is confirmed in service, holding Departmental enquiry would be necessary before passing order of termination/removal or dismissal on the ground of suppression or submitting false information in verification form.

(10) For determining suppression or false information attestation/verification form has to be specific, not vague. Only such information which was required to be specifically mentioned has to be disclosed. If information not asked for but is relevant comes to knowledge of the employer the same can be considered in an objective manner while addressing the question of fitness. However, in such cases action cannot be taken on basis of suppression or submitting false information as to a fact which was not even asked for.

(11) Before a person is held guilty of suppressio veri or suggestio falsi, knowledge of the fact must be attributable to him.

उक्त मार्गदर्शन के बिन्दु सं० 03 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियोक्ता पात्रता देखते समय तदसमय प्रचलित शासकीय आदेशों/निर्देशों/नियमों को विचार में लेगा।

हीरालाल के मामले में माननीय राज० उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के समय धारा 498 ए- 323 आई.पी.सी. के तहत दर्ज प्रकरण को वैवाहिक विवाद मानते हुये

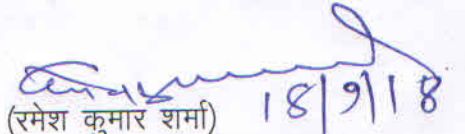
  
18/9/18

नियुक्ति के आदेश दिये जाने के साथ ही साथ सजायाबी की स्थिति में नियोक्ता को निर्णय पर पुर्नविचार की स्वतंत्रता दी।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे निम्न पद पर नियुक्ति नहीं दी जाकर एक ऐसे अधिकारी के रूप में (सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर ) नियुक्ति दी जानी है जिसका सीधा संबंध पुलिस विभाग से रहता है इस कारण हीरालाल के मामले में वर्णित तथ्य प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये पूर्णतया भिन्न प्रकट होते हैं। जहां तक अवतार सिंह के मामले का संबंध है इसमें शासकीय आदेशों/निर्देशों व नियमों का ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। राज0 सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के बिन्दु सं0 1(vii) में अंकितानुसार किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 498ए के तहत प्रकरण अन्वीक्षाधीन होने पर उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिये।


राज0 अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 13 में वर्णित नियम नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अवधि के संबंध में है, इस कारण उनके विस्तारपूर्वक विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के प्रकाश में पूर्ण मनन करने के बाद मे विभागीय कमेटी द्वारा पूर्व में व्यक्त किये गये मत से सहमत हूँ। अतः प्रार्थी जितेन्द्र कुमार बैरड़ को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र पाया जाता है।

  
(रमेश कुमार शर्मा) 18/9/18  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. श्री जितेन्द्र कुमार बैरड़ पुत्र श्री हेतराम निवासी वार्ड नं0 19, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन 18/9/18  
राजस्थान, जयपुर